

रीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स से निपटने के लिए इस बार बायोमैट्रिक अनिवार्य

फरवरी में संभावित रीट परीक्षा की तैयारियों पर शिक्षा विभाग का मंथन

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में सोमवार को रीट 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें फरवरी में संभावित रीट परीक्षा को लेकर आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।



स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में सोमवार को रीट 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई।

- परीक्षा में करीब 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान
- परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तय समय से एक घंटे पहले होगी एंट्री
- ब्लैकलिस्टेड कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों को इस बार शामिल नहीं करेंगे

अधिकारी (माध्यमिक व प्राथमिक) शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि रीट परीक्षा में 15 से 20 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने का

अनुमान है। इसके लिए जिला अधिकारी 5 जनवरी तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों में केवल राजकीय विद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों को वरीयता दी जाए। सभी परीक्षा केंद्रों को डे-टू-डे का प्लान फोल्ड सुपरवाइजर, वीक्षक, जोनल अधिकारी आदि की नियुक्ति करने की हिदायत भी दी गयी है। शिक्षा सचिव ने पेपर लीक एवं

डमी कैंडिडेट जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के लिए बायोमैट्रिक अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए प्रति सेंटर दो पुरुष एवं दो महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानी है। परीक्षा के प्रश्न पत्र जिला कोषागार में रखा जाना निर्धारित है, जिसके लिए वरिष्ठ आरएएस को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर एवं एसपी को इन्चार्ज बनाया जाना है। रीट परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक हर गतिविधियों की वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा केंद्रों पर नहीं की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को भी इससे बाहर रखा गया है। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्ल्यूटूथ सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एंट्री बंद रहेगी। शिक्षा सचिव ने सभी अधिकारियों को डे-टू-डे का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के नव निर्मित जिलों को लेकर नोटिफिकेशन अलग से जारी जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दी सांत्वना

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दो दिवसीय पाली, सिरौही और गुजरात प्रवास पर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के परिजनों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप परिवार को सांत्वना प्रदान की।

उन्होंने मार्टेड आबू नगर पालिका के अध्यक्ष और पूर्व जिला महामंत्री स्व. जालमगिरी के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को ढांडस बंधाया और दुख की इस घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। राठौड़ ने जालमगिरी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सिरौही समाजसेवी तारा राम माली के निधन पर उनके आवास भी पहुंचे और उनके परिजनों के साथ मुलाकात कर सांत्वना प्रदान की। राठौड़ ने पिंडवाडा प्रधान नितिन बंसल के स्वरूपगंज स्थित आवास पर पहुंचे और स्व. बाबू भाई बंसल के निधन पर शोक प्रकट किया।

इसके बाद मार्टेड आबू में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारण सदस्य नरपत चरण के आवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व. लालूदान चरण के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप परिवार को सांत्वना प्रदान की। मदन राठौड़ सुमेरपुर के भाजपा नेता कृपाशंकर के पुत्र सत्येंद्र की धर्म पत्नी के निधन पर उनके आवास पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान की।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास : जितेन्द्र सोनी

जयपुर। जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये पुराने साइनेज को हटाकर नये साइनेज लगाए जाएं। डॉ. सोनी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला यातायात प्रबंध समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।

उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों पर जारी फ्लाइटओवर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने जिले में एक्सिडेंट फ्री सड़क की चिन्हित एवं विकसित करने के भी निर्देश दिये ताकि उन्हें आदर्श सड़क के रूप में पहचान दिलाकर अन्य सड़कों एवं राजमार्गों पर भी सुगम यातायात एवं दुर्घटना रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने जयपुर जिले के शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर भारत सरकार के नये नोटिफिकेशन के अनुसार स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड लगाने, राजमार्गों के प्रोटोकॉल के निवारण करने एवं जिले में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने और राजमार्गों पर अनाधिकृत पार्किंग सहित रिफ्लेक्टिव टेप इत्यादि के उल्लंघनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को पिछली बैठक के बिन्दुओं की

- जयपुर जिले में इमरजेंसी मेडिकल प्लान तैयार किया जाएगा, सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे : सोनी
- कलेक्टर ने एक्सिडेंट फ्री सड़क चिन्हित करने और उसे विकसित करने के निर्देश दिये

अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बैठक में ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग करने, रूट उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने, टोल नाके पर शराब या नशा कर के चलाने वाले वाहन चालकों को पकड़ने तथा बेसहारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगा कर सर्दी में फोग से सेफ्टी के उपाय करने आदि पर भी चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस आयुक्त यातायात, पुलिस आयुक्त पश्चिम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व), श्री देवेन्द्र कुमार जैन सहित जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और मुस्कान फाउंडेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का अवलोकन किया



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार शाम को जवाहर कला केंद्र में सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में स्टॉल्स का अवलोकन किया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सोमवार शाम को राष्ट्रीय मेला 2024 पहुंचे। उन्होंने वहां देशभर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित "सरस राजसखी" का महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधियों से

महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार : हरिभाऊ बागडे

संवाद किया। मेले में आई देशभर की महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधिमंडल से भी उन्होंने इस दौरान बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह मेला "एक भारत श्रेष्ठ भारत" का अनुपम उदाहरण है। राज्यपाल बागडे ने मेले में लगे विभिन्न राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्टॉल का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह के मेलों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिला उत्पादों को बड़े स्तर पर बाजार मिलता है। उन्होंने वहां प्रदर्शित भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प, कारीगरी, वस्त्र उत्पादों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। राज्यपाल को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के भास्कर सांवत ने उनकी अगवाणी की। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने विभिन्न स्टॉल और उत्पादों के बारे में बताया।



बीते तीन दिन से प्रदेश में जारी शीतलहर और खराब मौसम के बाद सोमवार को दिन में धूप छिली, लेकिन धूप में तेजी नहीं होने के कारण ठंड तेज रही। राजधानी जयपुर में सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, इस कारण दृश्यता मात्र 30 मीटर रही। कोहरे व धुंध के कारण सुबह शहर में निकले लोगों को अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ी, लेकिन वे भी बेअसर सी लगती नज़र आई। फोटो-राष्ट्रदूत

समायोजित शिक्षा कर्मियों के लिए वर्ष 2025 से हो सकता है "नई पेंशन" का सफाया

जयपुर। राजस्थान सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2011 में समायोजित शिक्षा कर्मियों की सेवा निवृत्त पश्चात वेदना व पीडा के निराकरण के लिए "स्मरण संदेश" भेजा है जिसमें समायोजन तिथि के स्थान पर अनुदानित संस्था की नियुक्ति तिथि को ही मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देकर नव वर्ष में "ब्रेकर बनी" नई पेंशन स्कीम का साथ समायोजित शिक्षा कर्मी जगत से समाप्त हो सके, जिससे जीवन के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग शिक्षा कर्मी अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करे।

मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय ने आर.वी.आर ई एस नियम 2010 के अंतर्गत समायोजित कर्मियों को उनकी नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन

दिए जाने के मामले में "कर्मियों के डेटा" शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वित्त विभाग द्वारा गत चार माह से संकलित करने की प्रक्रिया जारी है। मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय एवं संचालक डीपी ओझा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि संदेश में यह भी वर्णित है 2011 में समायोजन पश्चात राज्य की अनेकों शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी हैं एवं निजी संस्थानों में कर्मचारी संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा उनके द्वारा कर्मचारियों को पीएफ राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है जिसके अभाव में राज्य के समस्त कर्मचारियों का "डेटा संकलन" होना मुश्किल सा लगता है। ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों को नागण्य मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के लिए आग्रह किया है।

11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने निजी खालेटी की करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को खूद-बूद किया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्वासी ने बताया जोन 8 में सांगानेर स्थित कूतरो की दागी में 2 बीघा कृषि भूमि पर तथा जोन-6 स्थित ग्राम नांगल का जैसा बोहरा (निवारू रोड) पर करीब 9 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों बसाने के लिए प्रेवल-मिट्टी की रोड, अवैध बाउंड्रीवाल समेत कई तरह के निर्माण कर लिए गए थे।

इसकी सूचना मिलते ही सोमवार को टीम ने दोनों जगह पर कार्रवाई करके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इन कॉलोनियों को बसाने के लिए काश्तकारों ने जे.डी.ए. प्रशासन से ना तो कोई निर्माण स्वीकृति ली और ना ही कृषि भूमि का रूपांतरण कराया।

मुरलीपुरा में सूने मकान से लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी

जयपुर। मुरलीपुरा इलाके में सूने मकान से लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय परिवार के सदस्य गांव गए हुए थे। इस संबंध में थाने में पीडित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदातस्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी

फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि मुरलीपुरा के सोनी का बाग निवासी विशाल पारीक ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी दादी का स्वर्गवास होने पर 26 दिसम्बर को वह गांव गए हुए थे। इस संबंध में थाने में पीडित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदातस्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी

अंदर घुसे। अलमारी के लॉक को तोड़कर तीस हजार रुपए के साथ ही गहनों में सोने के झुमर, चार अंगूठी, चार चूड़ी, एक रखड़ी, कानों का सैट, दो कड्डे, दो जोड़ी कानों की बाली, चार जोड़ी चांदी की पायजेब, चांदी के सिक्के, बर्तन, आंवला चोरी कर ले गए। रविवार को वापस लौटने पर चोरी की वारदात का पता चला।

राजस्थान में खनिज खोज कार्य का 5 साल का मास्टर प्लान बनेगा : टी. रविकांत

'मिनरल डिपोजिट और गुणवत्ता के बेहतर आंकलन से रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी होगी'

जयपुर। राजस्थान में खनिज खोज कार्य का पांच साल का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव माईस एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने बताया कि इससे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी आएगी और एक्सप्लोरेशन से खनिजों के डिपोजिट, गुणवत्ता और उपलब्धता का समय पर आंकलन होने से खनिज ब्लॉकों की समय पर और कारगर तरीके से नीलामी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध प्रयासों से ही राजस्थान केवल एक साल में ही मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से देश में शीर्ष पर आ गया है।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त सोमवार को खनिज भवन में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि आरएसएमईटी को राज्य के मिनरल एक्सप्लोरेशन के पांच साल का मास्टर प्लान शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा संघ प्रदेश है और एक्सप्लोरेशन का मास्टर प्लान बनने से योजनाबद्ध तरीके से खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनन और दोहन का कार्य हो सकेगा और इससे प्रदेश में रोजगार और



खनन विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त सोमवार को खनिज भवन में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की बैठक ली।

राजस्व के अवसर बढ़ सकेंगे। रविकान्त ने कहा कि राज्य में मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही केन्द्र व राज्य सरकार की संस्थाएं परस्पर सहयोग व समन्वय से एक्सप्लोरेशन कार्य को गति दे और कार्यों में डूफ्लिकेसी से बचा जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर निजी क्षेत्र की

एक्सप्लोरेशन कार्य में लगी संस्थाओं की भागीदारी भी तय की जाएगी। रविकान्त ने मास्टर प्लान सहित प्रदेश की खनिज संपदा से संबंधित सामग्री को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा जाए ताकि पारदर्शिता के साथ ही प्रदेश के माइनिंग सेक्टर में अधिक साधन संपन्न और तकनीकी दृष्टि से सशक्त प्रतिभागी आगे आ सकेंगे और इससे

प्रदेश को माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी से लेकर खनन तक बेहतर राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा और वैज्ञानिक ढंग से खनन होने से जीरो लॉस खनन हो सकेगा। उन्होंने आरएसएमईटी द्वारा तैयार की गई सलाहकार समिति को और अधिक सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि कार्य में गुणवत्ता निदेशक माईस भगवती प्रसाद

कलाल ने कहा कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में नवीनतम तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है ताकि मिनरल की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर नीलामी में बेहतर राजस्व प्राप्त हो सके।

आरएसएमईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि आरएसएमईटी द्वारा प्रदेश में एक्सप्लोरेशन से लेकर ड्रिलिंग, सेंपल एनालिसिस और विभागीय लेब के सशक्तिकरण के साथ ही तकनीकी रूप से विभागीय टीम को संसाधन उपलब्ध कराकर सक्षम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरएसएमईटी द्वारा ऑकलन के लिए ब्लॉक तैयार कर उपलब्ध कराए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हरीश मिश्री, एमईसीएल के आशीष सिंह आदि ने भी सुझाव दिए।

बैठक में संयुक्त सचिव आरू चोघरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी आलोक प्रकाश जैन, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील कुमार वर्मा के साथ ही वित्तीय सलाहकार गिरिश कछार, एसजी नितिन चौधरी, मनीष माथुर व जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम, आरएसएमएम आदि सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।